पांच राज्योंमें घटे मतदाता

वर्ष २०२७ में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, मणिपुर और गोवामें विधानसभाओंके चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए इन पांच राज्योंमें राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गयी है। खास बात यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाताओंकी संख्यामें १३.२४ प्रतिशतकी गिरावट आयी है। उपलब्ध ताजे आंकड़ोंके अनुसार इन पांच राज्योंको मिलाकर मतदाताओंकी संख्या लगभग १८.७१ करोड़से घटकर १६.४३ करोड़ रह गयी है। अर्थात् २.२९ करोड़ कमी आ गयी है। सबसे खास बात यह भी है कि इन पांच राज्योंमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां १३.२४ प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं। चुनावसे कुछ माह पूर्व मतदाता सूचियोंके एसआईआरने चुनावी राजनीतिके साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाको लेकर गम्भीर बहस छेड़ दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारको पदसे हटानेके लिए बड़े आन्दोलन शुरू हो गये हैं। एसआईआरके बाद राज्योंमें घटे मतदाताओंका चुनावी राजनीतिपर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। वैसे एसआईआरका मूल उद्देश्य मतदाता सूचीको शुद्ध करना, मृतकों, स्थानान्तरित हो चुके लोगों और दोहरी प्रविष्टियोंको हटाना तथा पात्र नागरिकोंको सूचीमें शामिल करना है लेकिन पांच चुनावी राज्योंमें अन्तिम मतदाता सूचीके आंकड़ोंने यह प्रश्न भी खड़ा कर दिया है कि इतनी बड़ी संख्यामें नाम हटनेके बाद यह सुनिश्चित कैसे होगा कि कोई वास्तविक और पात्र मतदाता मतदानके अधिकारसे वंचित नहीं रह जाय। एसआईआर प्रक्रियाको लेकर कुछ विसंगतियां सामने आयी हैं और गड़बड़ीके आरोप भी लगे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां मतदाताओंमें कमीकी भागीदारी ९० प्रतिशत है। उत्तर प्रदेशकी ४०३ सदस्यीय विधानसभा और उसकी राष्ट्रीय राजनीतिक महत्ताको देखते हुए मतदाता सूचीमें दो करोड़से अधिक मतदाताओंका कम होना राजनीतिको प्रभावित करने वाली घटना है। इससे चुनावी गणितके समीकरण प्रभावित होंगी। विशेष बात यह भी है कि उत्तर प्रदेशमें सूचीसे हटाये गये ८४ लाख अन्तिम सूचीमें वापस आ गये। इसके निहितार्थ भी अलग हैं। उत्तराखण्ड और गोवाकी स्थिति भी चिन्ताजनक है। मतदाता सूचीमें इतनी बड़ी संख्यामें बदलावसे राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोगके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती निष्पक्षताको लेकर है। आगामी चुनाव भारतीय लोकतंत्रमें मतदाता सूचीकी शुद्धता और नागरिकके मतदान अधिकारके बीच सन्तुलनकी बड़ी परीक्षा है। इसका सीधा प्रभाव २०२७ के विधानसभा चुनावोंकी विश्वसनीयतापर भी पड़ सकता है।

हवाई किरायेके नये नियम

केन्द्र सरकारने दूरदर्शी फैसला लेते हुए विमानन क्षेत्रके लिए जो नये नियम जारी किये हैं वह सर्वथा उचित और न्यायसंगत है। इसमें हवाई किरायेकी निगरानी और आवश्यकतानुसार कम्पनियोंको अस्थायी निर्देशका प्रावधान महत्वपूर्ण माना जायगा, क्योंकि इससे विमानन कम्पनियोंकी हवाई किरायेमें मनमानीपर अंकुश लगेगी। नये नियमके तहत टिकटका मूल किराया, कर और अन्य शुल्ककी स्पष्ट जानकारी देनेके लिए कम्पनियां बाध्य होंगी। नये नियम एक जनवरीसे लागू होगी जो ८९ वर्ष पुराने नियमोंकी जगह लेंगे। हालांकि सामान्य तौरपर टिकटकी कीमतोंपर कोई स्थायी सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन नियमित सेवाएं देने वाली विमानन कम्पनियोंको परिचालन लागत समेत विभिन्न कारकोंके आधारपर किराया तय करना होगा। इसके लिए किरायेका विवरण नागरिक उड्डयन महानिदेशालयको सौंपनेकी अनिवार्यता सार्थक पहल है। इन नियमोंके उल्लंघनपर एक करोड़ रुपयेतक जुर्मानेका प्रावधान है, जो विमानन कम्पनियोंके लिए कड़ा सन्देश है। साथ ही कुछ और कड़े प्रावधानोंको जोड़ा गया है जो सुरक्षाकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण है, जैसे हवाई क्षेत्रमें फोटोग्राफीपर एक लाख और उड़ते विमानसे तस्वीर लेनेपर दो लाख रुपयेतक जुर्माना हो सकता है। निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा प्रबन्धनका पालन नहीं करनेपर लाइसेंस निलम्बित या रद भी किया जा सकता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालयने त्योहारी सीजनको देखते हुए हवाई किरायेमें सात सौ फीसदीतक आरोप लगाने वाली याचिकापर जल्द सुनवाईके लिए बार-बार किये जा रहे आग्रहको सोमवारको तत्काल सुनवाईसे इनकार करते हुए दो-टूक कहा 'हवाई यात्रा न करें।' इस सम्बन्धमें न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अमरेश सिंहकी पीठका यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह अर्जी हवाई किरायेको नियंत्रित करनेकी मांगको लेकर है जो पहलेसे लम्बित एस. लक्ष्मी नारायणनकी जनहित याचिकामें शामिल है। हवाई किरायेको लेकर केन्द्र सरकारके नये नियमको कड़ाईसे लागू करनेकी जरूरत है।

लोक संवाद

महापुरुष

महोदय,-भारतमें बहुतसे महापुरुष हुए। इन महापुरुषोंने भारतको ही नहीं, बल्कि दुनियाको अच्छे मार्गपर ले जानेके लिए बहुतसे काम किये और दुनियाके लिए प्रेरक बने। इन्हीं महापुरुषोंमेंसे एक थे सरदार वल्लभभाई पटेल, जिनका जन्मदिन एकताकी भावनाको बढ़ानेके रूपमें भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेलने देशको आजाद करवानेके साथ-साथ देशकी एकताको मजबूत करनेमें मुख्य भूमिका निभायी थी। इन्होंने किसानोंको उनका हक अंग्रेजोंसे दिलानेके लिए काम किये थे। सरदार वल्लभ भाई पटेलको आज भी जिस मुख्य कार्यके लिए याद किया जाता है वह है देसी रियासतोंका एकीकरण। आज भारतको उनके विचारोंको कार्यरूप देनेकी जरूरत है। **-राजेश, वाया ईमेल।**

समाधान नहीं है करोंमें छूट देना

पिछले काफी समयसे भारतके शेयर बाजारोंमें विदेशी संस्थागत निवेशक बड़ी मात्रामें विदेशी मुद्रा बाहर ले जा रहे हैं। वर्ष २०२६-२७ में विदेशी संस्थागत निवेशक १.७ लाख करोड़ रुपयेकी बिकवाली कर चुके हैं, जिससे रुपयेपर दबाव बन रहा है। नीति-निर्माता चिन्तित हैं और भारतकी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

❐ प्रोफेसर अश्विनी महाजन

विदेशी संस्थागत निवेशकोंको आकर्षित करनेका एक महत्वपूर्ण तरीका करोंमें रियायत देनेसे संबंधित है। ५ जून २०२६ को सरकार और रिजर्व बैंकने स्वीकृत बांडोंसे होने वाले पूंजीगत लाभको पूर्वके १२.५ प्रतिशत पूंजीगत लाभ कर और आयकरसे छूट दी गयी है। इसके अलावा पूर्वमें जहां १५, ३० और ४० वर्षके ब्रांड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब उन्हें इसकी अनुमति दी गयी है। इसी प्रकार अन्य प्रकारकी रियायतें भी विदेशी संस्थागत निवेशकोंको दी गयी हैं। लेकिन उसके बावजूद इन निवेशकोंकी बिकवाली बदस्तूर जारी है। लेकिन यह जरूर हुआ है कि अब विदेशी संस्थागत निवेशकोंने सरकारी बांडोंमें निवेश बढ़ा दिया है। हालांकि सरकारने विदेशी संस्थागत निवेशकोंकी सरकारी ऋण प्रतिभूतियोंपर आयकर और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभोंसे छूट पहले ही दे दी है, अब उनकी मांग है कि उन्हें शेयरोंपर मिलने वाले पूंजीगत लाभों और अन्य लाभोंपर करसे छूट मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि यह छूट उनको पहले भी प्राप्त थी। दूसरे, विदेशी निवेशक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में भी कमी चाहते हैं। गौरतलब है कि इस साल बजटमें सरकारने 'फ्यूचर और ऑप्शन' (एफएंडओ) में एसटीटी को बढ़ाया था। पिछले सालोंमें एफएंडओकी वजहसे रिटेल इन्वेस्टरोंको बड़ा घाटा उठाना पड़ा था और इसका फायदा बड़ी विदेशी कम्पनियोंने उठाया।



करोंमें छूट अथवा अन्य सुविधाएं वास्तवमें विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवालीको नहीं रोक पायगी, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक देशमें करों अथवा नियमोंके कारण बिकवाली नहीं कर रहे, बल्कि दुनियामें बदलते हालात विदेशी निवेशकों द्वारा भारतमें उनके द्वारा शेयरोंकी बिक्रीका कारण बन रहे हैं। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और भारतसे इन संस्थागत निवेशकोंको खासा लाभ भी हुआ है। दशकोंतक विदेशी संस्थागत निवेशक भारतसे ३० से ४० प्रतिशत लाभ कमाते रहे हैं। वास्तवमें विदेशी संस्थागत निवेशक कई अन्य कारणोंसे अपने शेयर बेच रहे हैं।

सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) की रिपोर्टके अनुसार ४८५० करोड़ रुपयेका गैर-कानूनी लाभ 'जेनस्ट्रीट' सरीखी कम्पनीने एफएंडओसे कमाया। कुल मिलाकर कम्पनीने जनवरी २०२३ और मार्च २०२५ के बीच ३६७०० करोड़ रुपयेका लाभ कम्पनीने कमाया। यह लाभ वास्तवमें छोटे निवेशकोंका नुकसान है। तीसरे, विदेशी संस्थागत निवेशक चाहते हैं कि प्राइवेट एक्टिविटी फंड टाइगर ग्लोबलसे संबद्ध मामलेमें जो सुप्रीम कोर्टका निर्णय आया है, उसके बारेमें यह स्पष्ट करें कि २०२७ के पूर्वके निवेशपर भारतीय टैक्स लागू होंगे अथवा नहीं। गौरतलब है कि २०१७ में भारतने मॉरीशसके साथ दोहरे टैक्स वचन समझौतेमें बदलाव कर दिया था और मॉरीशसके रास्ते आने वाले निवेशपर कर लगानेका निर्णय लिया था। चौथे, विदेशी संस्थागत निदेशक अन्य प्रकारसे सुविधाएं चाहते हैं, जैसे टैक्स रिफंडको आसान बनाना, केवाईसी और लाभार्थीका खुलासा करनेकी अनिवार्यतासे मुक्त किया जाय। समझा जा सकता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक वे सभी सुविधाएं चाहते हैं जो अभीतक घरेलू निवेशकोंको उपलब्ध नहीं हैं। करोंमें छूट अथवा मुक्ति अथवा केवाईसी नियमोंमें छूट आदि देशके लिए अमंगलकारी होते हैं।

सर्वप्रथम हालांकि सरकारने पहलेसे ही सरकारी प्रतिभूतियोंमें निवेशसे आय और पूंजीगत लाभोंको कर मुक्त कर दिया है, यदि शेयरोंको भी करोंसे मुक्त किया जायगा तो उसका नुकसान सरकारी राजस्वको होगा, जिससे भारत सरकारका राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, जो महंगी बढ़ाने वाला और भविष्यकी पीढ़ियोंपर कर्ज भी बढ़ाने वाला है। गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशकोंको सरकारी बांडोंपर पूंजीगत लाभ और आयकरमें छूटसे लगभग १०,००० करोड़के राजस्वका नुकसान होगा। अब जब विदेशी निवेशक यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें शेयरोंपर होने वाले पूंजीगत लाभ और आयपर भी करकी छूट मिले तो यह नुकसान कई गुना होनेकी संभावना है। दूसरे, विदेशी निवेशकोंपर करमें रियायतको भारतीय निवेशकोंके साथ भेदभाव भी माना जा सकता है। इससे भारतीयों द्वारा बचतका प्रोत्साहन घटेगा, जिससे विदेशियोंपर निर्भरता बढ़ सकती है। तीसरे, विदेशी निवेशकोंकी एसटीटी कम करनेकी मांग, आय निवेशकके लिए अत्यंत घातक है। २०२६-२७ के बजटमें एसटीटी बढ़ानेके कारण एफएंडओमें छोटे निवेशकोंका आकर्षण कम हुआ है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकोंका अनुचित लाभ कम हुआ है। ऐसेमें एसटीटीको कम करनेकी मांग अनुचित तो है ही, यदि यह मांग मान ली जायगी तो छोटे निवेशकोंको बड़ा नुकसान जारी रहेगा। चौथे, विदेशी संस्थागत निवेशक चाहते हैं कि उनके लाभार्थी निवेशकोंकी जानकारीको गुप्त रखा जाय, इसलिए वे केवाईसी नियमोंसे छूट जाते हैं। इससे पहले यूपीए शासनकालमें विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्सके माध्यमसे भारतके शेयर बाजारोंमें पैसा लगाया जाता था। इस पद्धतिका खासा विरोध हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पार्टिसिपेटरी नोट्सके माध्यमसे आतंकवादी संघटनों एवं अन्य प्रकारकी गैर-कानूनी स्रोतोंसे पैसा भारतके शेयर बाजारमें आता है और उससे होने वाले लाभ भारतके खिलाफ ही इस्तेमाल किये जाते हैं। यदि केवाईसी नियमोंको शिथिल किया जायगा तो यह कानूनी रूपसे अनुचित ही नहीं, बल्कि गैर-कानूनी गतिविधियोंको बढ़ावा देने वाला और राष्ट्रीय सुरक्षाके लिए खतरे वाला होगा। अधिकांश आर्थिक विश्लेषक यह मानते हैं कि करोंमें छूट अथवा अन्य सुविधाएं वास्तवमें विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवालीको नहीं रोक पायगी, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक देशमें करों अथवा नियमोंके कारण बिकवाली नहीं कर रहे, बल्कि दुनियामें बदलते हालात विदेशी निवेशकों द्वारा भारतमें उनके द्वारा शेयरोंकी बिक्रीका कारण बन रहे हैं। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, और भारतसे इन संस्थागत निवेशकोंको खासा लाभ भी हुआ है। दशकोंतक विदेशी संस्थागत निवेशक भारतसे ३० से ४० प्रतिशत लाभ कमाते रहे हैं। वास्तवमें विदेशी संस्थागत निवेशक कई अन्य कारणोंसे अपने शेयर बेच रहे हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण अमेरिकामें ब्याज दरोंमें वृद्धि और अमेरिकी सरकारके बांडोंपर आकर्षक लाभ है। पूर्वमें अमेरिकामें फेडरल दर ०.२५ प्रतिशत तक थी। लेकिन हालके वर्षोंमें फेडरल रिजर्व (अमेरिकी केन्द्रीय बैंक) ने बढ़ती महंगीके चलते फेडरल दर बढ़ा दी है और वर्तमानमें यह ३.७५ से ४.० प्रतिशत है। ऐसेमें संस्थागत निवेशक वापसीका रुख कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारण भू-राजनीतिक अनिश्चितता है। ऐसी किसी भी स्थितिमें विदेशी निवेशक अपने घरेलू बाजारोंकी ओर रुख कर लेते हैं। इस स्थितिको अंतरराष्ट्रीय बाजारोंमें 'रन फॉर सेफ हेवन' कहा जाता है।

निवेशकों द्वारा बिकवालीका तीसरा प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारोंमें तेलकी बढ़ती कीमत और उसकी वजहसे दुनियाके दूसरे भागोंमें वित्तकी बढ़ती मांग है। चौथा, रुपयेका अवमूल्यन है। क्योंकि भारतीय रुपया पिछले समयमें काफी ज्यादा गिर गया था, इसलिए निवेशकोंको लाभ होनेपर भी डालरोंमें वह लाभ बहुत हो जाता है। इसलिए वे बाहरकी ओर रुख कर लेते हैं। पांचवां कारण यह है कि कई अन्य देशोंमें उभरते उद्योगोंकी वजहसे वहां निवेशकी संभावनाएं ज्यादा हैं। इस संदर्भमें दक्षिण कोरिया और ताईवानकी ओर विदेशी निवेशक रुख कर रहे हैं। भारतमें विदेशी निवेशपर लगने वाले कर अथवा केवाईसीके नियम अथवा अन्य भारतीय नियम विदेशी निवेशकों द्वारा बाहरका रुख करनेके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए करोंमें छूट देना हितकारी नहीं है।

सामूहिक सामाजिक चेतनाकी पराजय

पंचकूलाकी घटनाने एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया है, जिससे मुंह मोड़ना संभव नहीं है। आखिर बच्चोंके मनमें हिंसाके बीज कौन बो रहा है। बच्चों और किशोरोंमें हिंसक व्यवहारपर नियंत्रणकी कठिनाइयां इसके जोखिमको बढ़ा सकती हैं।

❐ योगेश कुमार गोयल

बचपनको मासूमियत, निश्छलता और खिलखिलाती मुस्कानका पर्याय माना जाता है। बच्चोंके हाथोंमें खिलौने अच्छे लगते हैं, पत्थर और ईंटें नहीं, किसीके प्रति नफरत और हिंसा नहीं। लेकिन जब आठ-दस वर्षकी उम्रके बच्चे भी किसी दूसरे मासूमकी जान लेनेपर उतारू हो जायं, तब सवाल केवल एक बच्चेके असामान्य व्यवहारका नहीं रह जाता, बल्कि पूरे सामाजिक परिवेश, पारिवारिक संस्कारों, शिक्षा व्यवस्था और हमारी बदलती जीवनशैलीका हो जाता है। हरियाणाके पंचकूलामें छह सालकी विशेष आवश्यकता वाली बच्चीपर तीसरी कक्षाके आठ वर्षीय छात्र द्वारा किया गया बर्बर हमला इसी भयावह वास्तविकताका आईना है। आरोपी छात्र बच्चीको एक खाली कक्षामें ले गया, वहां उसके बाल पकड़कर घसीटा, बेंचपर सिर पटका, लातें मारीं तथा ईंट, पत्थर और गमलेसे उसके सिर तथा चेहरेपर बार-बार प्रहार किये। करीब ९६ सैकेंडतक चली इस हिंसाका दृश्य कक्षामें लगे सीसीटीवी कैमरेमें दर्ज हुआ। सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि हमला करने वाला कोई व्यस्क अपराधी नहीं, बल्कि आठ वर्षका बच्चा है। यह घटना जितनी पीड़ित बच्चीके लिए भयावह है, उतनी ही उस बच्चेके मानसिक और सामाजिक विकासको लेकर भी गम्भीर चिन्ता पैदा करती है। आखिर इतनी छोटी उम्रमें किसी बच्चेके भीतर इतनी आक्रामकता कहांसे आती है। सवाल यह कि हमारे घरों, स्कूलों और समाजमें ऐसा क्या बदल रहा है कि बचपनकी भाषामें प्रेम और संवेदनाकी जगह हिंसा प्रवेश करती जा रही है।

इस घटनाने एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है, जिससे मुंह मोड़ना अब संभव नहीं है कि आखिर बच्चोंके मनमें हिंसाके बीज कौन बो रहा है। बच्चों और किशोरोंमें हिंसक व्यवहारका कोई एक कारण नहीं होता। परिवारमें हिंसा देखना, कठोर अथवा असंगत अनुशासन, भावनात्मक उपेक्षा, कमजोर अभिभावकीय निगरानी, साथियोंका दबाव, सामाजिक अलगाव और व्यवहारपर नियंत्रणकी कठिनाइयां इसके जोखिमको बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले सवाल परिवारोंसे है। आज अनेक घरोंमें बच्चोंको महंगे खिलौने, स्मार्टफोन, टैबलेट और मनोरंजनके तमाम साधन तो उपलब्ध करा दिये जाते हैं लेकिन उनके साथ बैठकर बातचीत करने, उनकी भावनाएं समझने और उनके व्यवहारको दिशा देनेका समय लगातार कम होता जा रहा है। माता-पिता अपनी व्यस्तताओंमें उलझे हैं और कई बार बच्चे अपनी भावनात्मक उलझनोंके साथ अकेले रह जाते हैं। बच्चा वही सीखता है, जो अपने आसपास बार-बार देखता है। यदि घरमें समस्याका समाधान संवादसे नहीं, बल्कि चीखने, धमकाने और हाथ उठानेसे होता है तो उसके लिए हिंसा धीरे-धीरे व्यवहारका स्वीकार्य तरीका बन सकती है।

दूसरा बड़ा सवाल डिजिटल दुनियाका है। मोबाइल फोन और इंटरनेटने बच्चोंके सामने ज्ञान और मनोरंजनके असंख्य अवसर खोले हैं लेकिन इसी दुनियामें हिंसक वीडियो, मारधाड़ वाले खेल और आक्रामक व्यवहारको महिमामंडित करने वाले दृश्य भी मौजूद हैं। समस्या तब गम्भीर हो जाती है, जब बच्चा बिना किसी निगरानीके घंटों ऐसी सामग्री देखता है और उसे यह समझाने वाला कोई नहीं होता कि पर्देपर दिखाई जाने वाली हिंसा वास्तविक जीवनमें किसीके मन और अस्तित्वको कितनी गहरी चोट पहुंचाती है। तीसरी चिन्ता बच्चोंमें संवेदनशीलता और सहानुभूतिके विकासकी है। आज हम बच्चोंको प्रतियोगितामें आगे निकलना, जीतना और दूसरोंसे बेहतर प्रदर्शन करना तो सिखा रहे हैं लेकिन हार स्वीकार करना, दूसरोंकी भावनाओंका सम्मान करना, कमजोरकी मदद करना और क्रोधपर नियंत्रण रखना कितना सिखा रहे हैं। क्या स्कूलोंमें नैतिक शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकोंतक सिमट गयी है। क्या बच्चोंको यह समझाया जा रहा है कि किसीको चोट पहुंचाना बहादुरी नहीं, कमजोरी है। किसी दूसरेकी पीड़ा देखकर मनमें करुणा पैदा होना ही मानवीय संवेदनाका आधार है। यहां स्कूलोंकी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पंचकूलाकी घटनाने सीसीटीवी कैमरोंकी मौजूदगी और वास्तविक निगरानीके बीचके अन्तरको उजागर किया है। कैमरे लगे होना सुरक्षा नहीं है, उनकी सतत निगरानी, समयपर हस्तक्षेप और जवाबदेही ही सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सवाल है कि एक छह सालकी बच्ची स्कूल परिसरमें एक अन्य छात्रके साथ ऐसी स्थितिमें कैसे पहुंच गयी, जहां उसपर लगातार हमला होता रहा और किसी शिक्षक या कर्मचारीको समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिली। यदि स्कूलमें शिक्षकोंकी कमी थी, एक शिक्षकको कई कक्षाओंकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी अथवा ड्यूटी व्यवस्थामें कोई खामी थी तो यह भी जांचका विषय है।

अभिभावकोंको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बच्चोंके व्यवहारमें अचानक आक्रामकता, दूसरोंको चोट पहुंचानेकी प्रवृत्ति, क्रोधपर नियंत्रण न रहना, पश्चातापका अभाव, जानवरों अथवा कमजोर बच्चोंके प्रति क्रूरता जैसे संकेतोंको सामान्य शरारत समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चोंको दंडित करनेके बजाय उनकी भावनाओंको समझना, उन्हें अपनी बात कहनेका अवसर देना और प्रेमके साथ स्पष्ट अनुशासन सिखाना जरूरी है। खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियां, सामूहिक सहभागिता और सामाजिक सेवा जैसी गतिविधियां भी उनमें सहयोग, धैर्य और सहानुभूति विकसित कर सकती हैं। इस घटनाने हमें एक कठोर सचाईसे रूबरू कराता है कि बच्चोंका भविष्य केवल अच्छे स्कूल, महंगी शिक्षा, आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओंसे सुरक्षित नहीं हो सकता। उसके लिए अच्छे संस्कार, भावनात्मक सुरक्षा, मानवीय संवेदना और जिम्मेदार अभिभावक भी उतने ही आवश्यक हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि पंचकूलामें एक आठ वर्षीय बच्चेने छह सालकी बच्चीपर हमला क्यों किया, बल्कि यह है कि हम ऐसी नौबत आनेसे पहले क्या कर रहे थे और भविष्यमें ऐसी घटनाएं रोकनेके लिए क्या करेंगे। जिस उम्रमें बच्चोंको अक्षर ज्ञान, दोस्ती, खेल और मानवीय रिश्तोंका अर्थ समझना चाहिए, उस उम्रमें यदि उनके हाथोंमें ईंट और पत्थर दिखाई देने लगें तो यह केवल एक परिवार या स्कूलकी विफलता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक सामाजिक चेतनाकी पराजय है। हमें तय करना होगा कि बच्चोंको केवल प्रतियोगितामें जीतना सिखाना है या इंसानियतके साथ जीना भी क्योंकि बचपन यदि हिंसक हो गया तो भविष्य सभ्य कैसे होगा और यदि स्कूलोंमें बच्चे सुरक्षित नहीं तो फिर उनके सुरक्षित भविष्यकी गारंटी कौन देगा।



आत्मा की शुद्धि

❐ अनुज आचार्य

भारतीय सनातन संस्कृतिमें मनुष्यकी महानताका आधार उसका धन, पद, कुल अथवा प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि उसके सद्कर्म, संस्कार और आचरण हैं। बाहरी वैभव व्यक्तिको आकर्षक बना सकता है, लेकिन उसके चरित्रकी वास्तविक पहचान उसके व्यवहारसे होती है। ईश्वरकी आराधना करना श्रद्धा है, किन्तु उसके बताये सद्गुणोंको जीवनमें उतारना सच्ची साधना है। सनातन दर्शन मनुष्यको अपने अंतर्मनकी शुद्धि और आत्मिक उन्नतिका मार्ग दिखाता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार व्यक्तिके विवेकको ढक देते हैं, जबकि क्षमा, संतोष, विनम्रता, दया और परोपकार उसके व्यक्तित्वको गरिमा प्रदान करते हैं। धार्मिक ग्रंथोंका ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह हमारे आचरणमें दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति नियमित पूजा करता है, लेकिन दूसरोंके अधिकारोंका हनन करता है, असत्य बोलता है तो उसे अपनी धार्मिकताके वास्तविक स्वरूपपर विचार करना चाहिए। सच्चा धर्म वह है, जो मनुष्यको बेहतर इनसान बनाये। भगवान श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात् मनुष्यका अधिकार कर्म करनेमें है, फलपर नहीं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्योंका निर्वहन निष्ठा और समर्पणसे करना चाहिए, न कि केवल लाभ अथवा प्रशंसाकी अपेक्षासे। जब कर्म स्वार्थ और अहंकारसे ऊपर उठकर कर्तव्यबोध तथा लोककल्याणकी भावनासे किया जाता है, तब वह कर्मयोग बन जाता है। शिक्षकका विद्यार्थियोंको ज्ञान और संस्कार देना, चिकित्सकका रोगियोंकी सेवा करना, किसानका अन्न उपजाना और सैनिकका राष्ट्रकी रक्षा करना अपने-अपने क्षेत्रमें कर्मयोगके उदाहरण हैं। इस प्रकार अपने दायित्वको ईमानदारीसे निभाना भी ईश्वरके प्रति समर्पणकी अभिव्यक्ति बन सकता है। गीताका एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश है- योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात् कर्मोंमें कुशलता ही योग है। आध्यात्मिकताका अर्थ संसारसे विमुख होना नहीं, बल्कि संसारमें रहते हुए अपने कर्तव्योंको विवेक, निष्ठा और सद्भावसे निभाना है। भाग्यके भरोसे निष्क्रिय बैठनेके बजाय पुरुषार्थ करना आवश्यक है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रणमें नहीं होतीं, लेकिन हमारा प्रयास, दृष्टिकोण और व्यवहार हमारे व्यक्तित्वको दिशा देते हैं। ईश्वरपर विश्वासका अर्थ चमत्कारकी प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि श्रद्धाके साथ कर्म करना और कठिन समयमें धैर्य बनाये रखना भी है। सच्ची आस्था मनुष्यको कर्महीन नहीं, बल्कि अधिक साहसी, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। श्रेष्ठ व्यक्तित्वकी सबसे सुन्दर अभिव्यक्ति सेवा और करुणामें दिखाई देती है। किसीकी सहायता करके उसे अपमानित करना परोपकार नहीं, वास्तविक सेवा वह है, जिसमें दूसरेकी गरिमा और आत्मसम्मान सुरक्षित रहें।

तनावको नियंत्रित करनेके प्रति जागरूकता

❐ श्वेता गोयल

सुविधाएं बढ़नेके साथ मनुष्यका लगातार घटता सुकून आधुनिक जीवनकी सबसे बड़ी विडंबनाओंमेंसे एक है। तकनीकने दूरियोंको समेट दिया है, संचारको त्वरित बना दिया है और जीवनको सुविधाजनक बनानेके असंख्य साधन उपलब्ध करा दिये हैं लेकिन इसके बावजूद मनुष्य पहलेसे कहीं अधिक मानसिक दबाव, बेचैनी, असुरक्षा और तनावसे घिरा दिखाई देता है। सुबह आंख खुलनेसे लेकर रातको सोनेतक जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक चिन्ताओं, नौकरीकी अनिश्चितता, पारिवारिक उलझनों और सामाजिक अपेक्षाओंका ऐसा सिलसिला चलता रहता है, जिसमें व्यक्ति स्वयंके लिए समय निकालनातक भूल जाता है। विडंबना यह है कि तनावको आजकल सफल और व्यस्त जीवनकी स्वाभाविक कीमत मान लिया गया है जबकि लगातार बना रहने वाला तनाव धीरे-धीरे शरीर और मन दोनोंको भीतरसे कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि तनाव अब केवल व्यक्तिगत परेशानी नहीं, गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है।

इसी चुनौतीके प्रति जागरूकता बढ़ानेके उद्देश्यसे प्रतिवर्ष नवंबरके पहले बुधवारको राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस (नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे) मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस ४ नवंबरको है। इसकी शुरुआत वर्ष १९९८ में ब्रिटेनकी इंटरनेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट असोसिएशनने की थी। इसका मूल उद्देश्य लोगोंको तनावके कारणों, लक्षणों और दुष्प्रभावोंसे परिचित कराना तथा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवनमें तनावको पहचानने और प्रभावी ढंगसे नियंत्रित करनेके उपायों के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संघटनके अनुसार तनाव किसी कठिन परिस्थितिके कारण उत्पन्न होने वाली चिन्ता अथवा मानसिक दबावकी स्थिति है। यह जीवनकी चुनौतियों और सम्भावित खतरोंके प्रति शरीरकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। परीक्षा, प्रतियोगिता, नौकरीके साक्षात्कार अथवा किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारीके दौरान उत्पन्न होने वाला हल्का तनाव व्यक्तिको सतर्क, सक्रिय और लक्ष्यके प्रति एकाग्र बना सकता है।

तनावकी स्थितिमें शरीरकी प्राकृतिक 'फाइट ऑर फ्लाइट' यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। मस्तिष्क खतरे अथवा दबावका संकेत मिलनेपर शरीरमें एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोनके स्रावको प्रभावित करता है। हृदय गति और रक्तचाप बढ़ सकते हैं, सांस तेज हो सकती है, मांसपेशियोंमें खिंचाव आने लगता है और शरीर तत्काल प्रतिक्रिया देनेके लिए तैयार हो जाता है। आपातकालीन परिस्थितियोंमें यह प्रतिक्रिया उपयोगी होती है लेकिन जब यही स्थिति लम्बे समयतक बनी रहती है तो शरीरकी सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगती है। लगातार तनावसे नींदमें बाधा, सिरदर्द, थकान, पाचन संबंधी समस्याएं, चिड़चिड़ापन, एकाग्रतामें कमी और निर्णय लेनेकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। दीर्घकालिक तनाव उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं तथा पहलेसे मौजूद बीमारियोंको और गम्भीर बनानेमें भी योगदान दे सकता है। तनावका प्रभाव केवल मनतक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीरपर पड़ता है। तनावका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके शुरुआती संकेत अक्सर सामान्य थकान, कामका दबाव अथवा अस्थायी मनोदशा समझकर नजरअंदाज कर दिये जाते हैं। कई लोग स्वयंको सामाजिक गतिविधियोंसे अलग कर लेते हैं और अपनी परेशानी दूसरोंसे साझा करनेसे भी बचते हैं। यदि लम्बे समयतक तनाव बना रहे तो चिन्ता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत